(c) the Government's reaction to such companies?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) So far 275 companies have submitted proposals for dilution of equity in accordance with the directives issued by the Reserve Bank of India under Section 29(2) (a) of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973.

- (b) While no company has refused to comply with the FERA directive, firm proposals have not yet been received from 7 companies.
- (c) Directives issued under the FERA are statutory in Character and failure to comply with them would attract the penal provisions of the Act.

Reservation of S.C./S.T. in S.T.C./ M.M.T.C./P.E.C.

3335 SHRI SHIV SAMPATI RAM:
Will the Minister of COMMERCE
AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state;

- (a) whether it is a fact that Ministry of Home Affairs vide their Memorandum No. 5/1/63-SCT(1) dated 4th March, 1964 provides reservation for SC & ST in the services under the Public Sector Undertakings like State Trading Corporation etc;
- (b) whether it is also a fact that O. M. No. 27/2/71-Estt. (SCT) dated 27th November, 1972 provides reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in posts filled by Promotion—Promotions on the basis of Seniority.cum.Fitness;
- (c) if so, what was the total number of employees in State Trading Corporation, Minerals and Metals Trading Corporation and Project Equipment Corporation etc. during the year 1965 and total number of SC & ST employees amongst them; and

(d) how many employees have been recruited and promoted in Corporations mentioned above since 1965 and upto 31st December 1977 and what is the proportionate share of SC & ST in each category out of the total number of employees and detail thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सुपर बाजार द्वारा निर्माणकर्ताओं की बजाय विजीतियों से वस्तुएं सरीदा जाना

3336. श्री खन्नदेव प्रसाद वर्मा: क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और स्वकारिता मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि कोण परेटिव स्टोसं लिमिटेड दिल्ली द्वारा चलाये ाने वाले सुपर बाजार में वेची जाने वाली वस्तुये सीधे निर्माणकर्तामां से न लेकर विचौियो से खरीदी जाती है जिससे उपभोक्तामा को म्राधिक कीमत वेनी पडती है और मृपर बाजार को भी धाटा हो रहा है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रास्य में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): को आपरेटिव न्टोर लिमिटेड (मुपर वाजार), दिल्ली विनिर्मित वस्तुम्रो की खरीद माम तौर पर सीधे विनिर्माताभ्रों ने भ्रथवा उनके द्वारा प्राधिकृत एजेंटों से वस्तुम्रों ने भ्रथवा उनके द्वारा प्राधिकृत एजेंटों से वस्तुम्रों ने भ्रथवा उनके क्वारा प्राधिकृत एजेंटों से वस्तुम्रों ने प्रवात की मादि का संबंध है, ये वस्तुम्रे राष्ट्र स्तरीय सहकारी संगठनों, जहां-कही सम्भव है, तथा कमीमान एजेंटों/बोक विकेताभ्रों से मुनासिव मूल्यों पर खरीवी उन्ती है। इसमे सुपर बाजार को हानि नहीं हो रही है। इसके द्वारा बेची जाने वाली यस्तुम्रो के फुटकर मूल्य भ्रामतौर पर खले बाजार में वल रहे मल्यों से कम होते है।